

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]
No. 599]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2005/ज्येष्ठ 24, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2005/JYAISTHA 24, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2005

का.आ. 822 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आर. सी. चोपड़ा की अध्यक्षता में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन इस बात का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए करती है कि दीनदार अंजुमन को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

[फा. सं. 14017/8/2005-एनआई-III]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2005

S.O. 822 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Deendar Anjuman as unlawful association consisting of Mr. Justice R.C. Chopra, Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 14017/8/2005-NI-III]

A. K. JAIN, Jt. Secy.